

50.50 लाख के विकास कार्यों का बकानी में लोकार्पण पंचायत भवन और कालाजी महाराज वाली पुलिया का विधायक मोहन शर्मा ने किया लोकार्पण

ओमप्रकाश राठौर- समय जगत, खंडवा। ग्राम पंचायत बकानी में ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण विधायक मोहन शर्मा द्वारा विधिवत किया गया। इस अवसर पर नवनिर्मित पंचायत भवन एवं कालाजी महाराज वाली पुलिया को ग्रामीणों को समर्पित किया गया। वहीं ग्राम उमरी में 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाई स्कूल भवन का भी लोकार्पण किया गया। एक ही कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा। ग्राम पंचायत बकानी में 37 लाख 50 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। पंचायत भवन की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत बकानी रही है। नए भवन के



निर्माण से ग्रामीणों को पंचायत संबंधी कार्यों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा। पंचायत के प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी सहूलियत होगी। ग्रामीणों को अब पंचायत स्तर की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इसी क्रम में ग्राम पंचायत क्षेत्र में कालाजी महाराज

वाली पुलिया का निर्माण 13 लाख रुपए की लागत से पूर्ण कराया गया है। इसका निर्माण भी ग्राम पंचायत बकानी को निर्माण एजेंसी बनाकर कराया गया। पुलिया निर्माण से ग्रामीणों के आवागमन में सुविधा होगी। बारिश के दौरान रास्ते में पानी भरने और आवागमन बाधित होने की समस्या से भी ग्रामीणों को राहत

मिलेगी। क्षेत्रवासियों के लिए यह पुलिया लंबे समय से आवश्यक विकास कार्यों में शामिल थी। पंचायत भवन और कालाजी महाराज वाली पुलिया की कुल निर्माण लागत 50 लाख 50 हजार रुपए है। दोनों विकास कार्य पूर्ण होने के बाद विधायक मोहन शर्मा ने इनका लोकार्पण कर ग्रामीणों को समर्पित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत का आभार व्यक्त किया। उमरी में 1.39 करोड़ की लागत से बने हाईस्कूल भवन का भी लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ग्राम उमरी में 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाई स्कूल भवन का भी लोकार्पण किया गया। नवीन भवन मिलने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होने की उम्मीद है।

अवैध शराब के खिलाफ बोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

समय जगत, बोड़ा। जिले में जुआ, मादक पदार्थ स्मैक एवं गांजा तथा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 216 लीटर अवैध देशी मदिरा शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 20 हजार रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के निर्देशन में जिलेभर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के.एल. बंजारे के निर्देशन एवं एसडीओपी नरसिंहगढ़ प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोड़ा उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 9 सितंबर को थाना क्षेत्र के ग्राम कड़िया एवं ग्राम गुलखेड़ी में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई



के दौरान पुलिस ने विक्रम पिता नाथूलाल सासी, नरोत्तम पिता मोड़ सिंह तथा वीरू पिता लाखन सासी निवासी गुलखेड़ी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 216 लीटर देशी मदिरा शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। गिरफ्तार

आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहीं मामले में फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेन्द्र सिंह राजपूत, उप निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद मिश्रा, उप निरीक्षक हुकुम सिंह, सर्जिन समीर खान, सर्जिन मधुसूदन शर्मा सहित पुलिस टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

साक्षिप्त समाचार महिला एवं बाल विकास आयुक्त श्री संदीप ने इंदौर में बाल संस्थाओं का किया निरीक्षण

समय जगत, भोपाल। आयुक्त महिला एवं बाल विकास संदीप जी.आर. ने पदभार संभालते ही विभागीय योजनाओं और संस्थाओं की जमीनी स्थिति की पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार को उन्होंने इंदौर पहुंचकर छावनी स्थित राजकीय बाल आश्रम, ऑब्जर्वेशन होम (संरक्षण गृह), स्पेशल होम और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों और समस्याओं को जाना तथा संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। राजकीय बाल आश्रम के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने वहां निवासरत बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना।



रतलाम में निवेश की संभावनाओं को लेकर मयूरी चोरडिया ने मंत्री चेतन्य काश्यप से की चर्चा



रतलाम, समय जगत। लंदन में 15 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवाइजर एवं कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत सनराइज फाइनंस, लंदन की एमडी मयूरी चोरडिया ने रतलाम प्रवास के दौरान सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप से मुलाकात की। उन्होंने रतलाम में विकसित किए जा रहे निवेश क्षेत्र में संभावित निवेश एवं औद्योगिक अवसरों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। रतलाम से जुड़ी मयूरी चोरडिया ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा निवेशकों एवं उद्योगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, विभिन्न योजनाओं, प्रोत्साहनों तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मंत्री श्री काश्यप से प्राप्त की। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ मयूरी चोरडिया लंबे समय से वित्तीय परामर्श एवं कंसल्टेंसी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने राजस्थान में निवेश किया है तथा मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर रुचि व्यक्त की है। मंत्री श्री काश्यप ने मध्यप्रदेश में उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों तथा निवेशकों को लिए उपलब्ध सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और नए निवेश के माध्यम से रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इससे मयूरी चोरडिया की मुलाकात रतलाम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों की रुचि बढ़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वित्तीय क्षेत्र में उनके व्यापक अनुभव और निवेश संबंधी रुचि से रतलाम में भविष्य में नए औद्योगिक एवं व्यावसायिक अवसरों की संभावनाओं को बल मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले सांसद- विधायक नर्मदापुरम-पिपरिया मार्ग के चौड़ीकरण सहित विविध सड़क, सिंचाई और कृषि परियोजनाओं पर हुई चर्चा

समय जगत, इटारसी। मुख्यमंत्री निवास, भोपाल में होशंगाबाद-नरसिंहपुर लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आत्मीय भेंट कर लोकसभा क्षेत्र के विकास एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री के समक्ष नर्मदापुरम से पिपरिया मार्ग के चौड़ीकरण, नानपा-कुलड़ा मार्ग, बनखेड़ी-झिरपा सहित क्षेत्र के आवश्यक मार्गों के निर्माण का विषय प्रमुखता से रखा। उन्होंने इन मार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण से क्षेत्र के नागरिकों को मिलने वाली बेहतर आवागमन सुविधा और विकास की संभावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बैठक के दौरान सांसद ने सोहागपुर नहर एवं देवरी उद्देह सिंचाई परियोजना को गति देने तथा किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही



बोहानी में कृषि आधारित प्रकल्प स्थापित करने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्र में कृषि, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने करेली में स्वीकृत शासकीय

आईटीआई का संचालन शीघ्र प्रारंभ किए जाने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया, ताकि क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त

सांसद ने धान का समर्थन मूल्य पर उपाजन सुनिश्चित करने के संबंध में भी मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों की अपेक्षाएं रखीं। उन्होंने विधायक विजय पाल सिंह के साथ मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों की संभावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए क्षेत्र के औद्योगिक विकास कार्यों के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के विकास, किसानों की सुविधा, युवाओं के रोजगार और बेहतर आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार के साथ निरंतर समन्वय करते हुए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

17 सितंबर से नर्मदा पथ पर आएगा पूरा समाज ग्राम म्हरा गांव से प्रारंभ होगा सेवा का अभियान

नर्मदापुरम, समय जगत। इस जिले नर्मदापुरम में मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले धार्मिक जनों के लिए इस जिले में अब नर्मदा सेवा पथ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस माह की 17 सितंबर से ग्राम महारागंव से शुरुआत होगी। इस अभियान में जन भागीदारी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है सबसे बड़ी भारी बात आम जन को भी इसमें जोड़ा जाएगा अभियान की रूपरेखा तैयार करने के दौरान राजस्वभा सांसद माया नारोलिया दादा गुरु महाराज नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव पूर्व विधायक एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी सविता दीवान शर्मा पूर्व संभागीय मैनेजर जीएस डोंगी कलेक्टर सोमेश मिश्रा के साथ इस जिले की जन अभियान परिषद के कोस्टेबल तिवारी कोकिला चतुर्वेदी विभिन्न



समितियों मैदान में उतरेंगे। धार्मिक जनों के लिए सरल मार्ग स्वच्छता वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण आश्रय और स्वास्थ्य सुविधाओं को एक साथ जोड़कर पूरे परिक्रमा पद को सेवा भाव के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इस अभियान के अंतर्गत पौधारोपण विशेष जोर दिया गया है। परिक्रमा के आसपास पहले साल 51 000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और इनके संरक्षण और निगरानी के लिए देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय

समितियों को दी जाएगी। पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति सदस्य श्रीमती सविता दीवान शर्मा ने बताया कि स्थानीय जन अभियान परिषद समिति और विभिन्न समितियां गांव में लोगों से संपर्क करेंगे स्थानीय टास्क फोर्स की स्थिति सफाई वृक्षों की देखभाल और धार्मिक जनों की जरूरत की जानकारी जताकर प्रशासन तट पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न नर्मदा परिक्रमा पद की लंबाई करीब 223 किलोमीटर है यह मार्ग 68 गांव से होकर गुजरता है। मार्ग में 6 प्रमुख संगम स्थल मां नर्मदा में मिलने वाली 23 सहायक नदियां और 13 स्वास्थ्य केंद्र भी चिह्नित किए गए हैं। इन सभी स्थानों को अभियान से जोड़कर धार्मिक चुनाव को बेहतर मार्गदर्शन और इनके संरक्षण और निगरानी के लिए दीक्षा में कार्य किया जाएगा।

मिट्टी से गणेश प्रतिमा निर्माण का दिया प्रशिक्षण विद्यार्थियों ने सीखी पर्यावरण हितैषी गणेश प्रतिमा बनाने की कला

समय जगत, खंडवा। नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मिट्टी से गणेश प्रतिमा निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 27 स्थित भवानी माता वार्ड के ठक्कर बाबा स्कूल तथा वार्ड क्रमांक 03 स्थित सूरज कुंड वार्ड के गायत्री विद्यापीठ स्कूल में नगर निगम की IEC टीम द्वारा विद्यार्थियों को मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को मिट्टी से गणेश प्रतिमा तैयार करने की विधि समझाई गई तथा पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा के महत्व को जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण में सहभागिता करते हुए स्वयं मिट्टी से गणेश प्रतिमा



बनाने की प्रक्रिया सीखी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं को प्राथमिकता दे तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं हानिकारक रसायनों से निर्मित प्रतिमाओं के उपयोग

से बचें। इससे धार्मिक आस्था के साथ-साथ जलस्रोतों एवं पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। नगर निगम की IEC टीम द्वारा स्कूलों एवं विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं हानिकारक रसायनों से निर्मित प्रतिमाओं के उपयोग

सुविधा विहीन शमशान घाट से अंतिम संस्कार में हो रही है दिक्कतें



समय जगत, गंजबासोदा। आजादी के कई साल बाद भी ग्रामीण अंचलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। कुछ इसी तरह की कहानी ग्राम पंचायत रबरयाई के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिरावदा की बनी हुई है। बरसात में यहां के सुविधा विहीन

शमशान घाट में एक आदिवासी महिला का अंतिम संस्कार करना ग्रामीण और उनके परिजनों को भारी पड़ गया। ग्राम सिरावदा के ग्रामीणों का आरोप है कि बरसात के दिनों में अगर किसी ग्रामीण की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को उनके

अंतिम संस्कार करने में काफी सुविधा झेलनी पड़ती है। शुक्रवार के दिन ग्राम की मुल्ले बाई आदिवासी का निधन हो गया था। इसके बाद उनके परिजनों को उनके अंतिम संस्कार करने में काफी सुविधा हुई क्योंकि ना तो शमशान घाट तक जाने के लिए पक्की सीसी सड़क का निर्माण कराया गया था और ना ही उसके एक हिस्से में टैनसेट था। शुक्रवार के दिन जोरदार बारिश भी हुई, जिस कारण अंतिम संस्कार में काफी दिक्रत झेलनी पड़ी। यह ग्राम जनपद पंचायत गंजबासोदा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रबारी से संबंध सिरावदा है। इसकी जनसंख्या लगभग 870 है। यहां तो कई कमियां हैं और खास बात यह है कि इसी से संबंध दो गांव और आते हैं और उनमें भी शमशान घाट की स्थिति कुछ इसी तरह बनी हुई है।

कार्यकर्ता सहायिका का तीन दिन का वेतन काटने, सुपर वाइजर निलंबित परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी

व्यावरा / नरसिंहगढ़। संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास भोपाल संभाग हरिकृष्ण शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. ईच्छा गढ़पाले द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना महिला बाल विकास कुरुवर अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र गीलाखेड़ी - 3 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण माह की गतिविधि संचालित होना पाई गई, परंतु केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति अत्यंत कम पाई गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण ट्रेकर पर हितग्राहियों का डाटा अपडेट नहीं किया गया था। अत्यवस्थाओं को देखते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. गढ़पाले द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का तीन दिवस का वेतन काटने, सुपरवाइजर श्रीमती वंदना शर्मा को निलंबित करने तथा परियोजना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

सीएमओ द्वारा सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने दिए गए आवश्यक निर्देश

समय जगत, इटारसी। विगत दिनों विधायक द्वारा समीक्षा बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यवस्था में सुधार एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री सुरेखा जाटव द्वारा वार्ड क्रमांक 13 एवं 14, न्यास कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वार्ड में इयूटी से अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य से पृथक् करने की कार्यवाही की गई। सीएमओ ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।



उपस्थित रहकर जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें। निरीक्षण के दौरान न्यास कॉलोनी के पार्कों का भी जायजा लिया गया। पार्कों की वर्तमान व्यवस्था एवं रखरखाव को देखते हुए उनकी

जवाबदारी वाटर सप्लाय में कार्यरत पंप ऑपरेटर्स को दी गई है। उन्हें पार्कों की नियमित साफ-सफाई, पानी एवं आवश्यक रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वार्डवार निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी। नागरिकों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है।

संपादकीय

पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है आतंकवाद पर लगाम

देश के लिये आतंकवाद लंबे समय से बड़ा मुद्दा है। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के लिए अनुकूल माहौल जरूरी है। जिसके लिये पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है। सीमा पार से आतंकियों को प्रशिक्षण देना, उन्हें भारत में हिंसा फैलाने के लिए भेजना और आतंकी घटनाओं के बाद भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना उसकी नीति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर कार्रवाई की एक कीमत होती है और अब पाकिस्तान को अपने इसी रवैये की कीमत पानी के मोर्चे पर चुकानी पड़ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो कठोर निर्णय लिया, उसके प्रभाव अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। लद्दाख में सिंधु नदी पर चेक डैम का निर्माण इसी बदलती तस्वीर का संकेत है। लद्दाख के उपशी में सिंधु नदी पर तैयार किया गया पहला रॉक चेक डैम केवल पानी रोकने वाली एक छोटी परियोजना नहीं है। यह बदलते भारत की सोच और उसकी जल नीति का प्रतीक है। जिस सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत ने दशकों तक संधि की मर्यादाओं का पालन किया, उसी नदी के पानी का अपने लोगों के हित में बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में अब कदम बढ़ रहे हैं।

उपशी में तैयार चेक डैम में पानी जमा होना और उसके माध्यम से आसपास के खेतों तक सिंचाई पहुंचाने की संभावना लद्दाख जैसे दुर्गम और पानी की कमी वाले क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शुरुआत भर है। लद्दाख में सिंधु नदी पर 36 और चेक डैम बनाने की तैयारी की जा रही है। इनमें लेह में सात हिमालयन रॉक चेक डैम और करगिल में 29 चेक डैम प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 56 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। लद्दाख की परिस्थितियां किसी से छिपी नहीं हैं। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में पानी का संकट हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। प्राकृतिक चट्टानों से तैयार की गई ऐसी संरचनाएं पानी को रोकने, भूजल स्तर सुधारने और खेतों तक पानी पहुंचाने में उपयोगी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाए जा रहे इन ढांचों से जल संरक्षण और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश भी दिखाई देती है। ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए तो उससे जुड़े शेष मुद्दों का समाधान भी हो सकता है।

विश्व को भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन से दिया शांति का संदेश

सौरभ वाष्पाण्य

पूरा विश्व इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें भारत के नई दिखी में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल राष्ट्राध्यक्षों की एक कुटनीतिक बैठक भर नहीं है। यह सम्मेलन बदलती हुई विश्व व्यवस्था, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता, युद्धों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों और विकासशील देशों की बढ़ती आकांक्षाओं के बीच भारत की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडल में होने वाले 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस बार उसका केंद्रीय विषय है (ब्रिडिंडां पारं रंसिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी) अर्थात लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण 7 भारत ने अपनी अध्यक्षता को ह्यूमैनिटी फर्स्ट की सोच से जोड़ते हुए ब्रिक्स को अधिक व्यावहारिक और विकासोन्मुख मंच बनाने पर जोर दिया है। यही इस सम्मेलन से भारत का पहला और सबसे बड़ा संदेश है- विश्व राजनीति को टकराव से निकालकर सहयोग की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। आज विश्व के अनेक हिस्से संघर्ष की आग में झुलस रहे हैं। यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया की अस्थिरता और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जटिल बना दिया है। ऐसे समय में भारत लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ब्रिक्स का मंच भारत को यह संदेश देने का अवसर देता है कि अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं और राष्ट्रीय हितों वाले देश भी संवाद और सहयोग के माध्यम से सझा समस्याओं पर काम कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति का मूल स्वर न तो किसी एक शक्ति-गुट के साथ खड़ा होना है और न किसी दूसरे गुट के विरोध में खड़ा होना। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है। यही रणनीतिक स्वायत्तता आज भारत की सबसे बड़ी कुटनीतिक ताकत बनती दिखाई दे रही है। ब्रिक्स अब केवल पांच देशों का आर्थिक समूह नहीं रह गया है। इसके विस्तार ने इसे विकासशील और उपरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना दिया है। भारत इस मंच के माध्यम से ग्लोबल साउथ की उस आवाज को मजबूती देना चाहता है। संलंबे समय से वैश्विक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करती रही है। जंगल राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की नियंत्रण प्रक्रिया में विकासशील देशों की वास्तविक अधिकार और जनसंख्या-आधारित ताकत के अनुरूप प्रतिनिधित्व का सवाल लगातार उठता रहा है। भारत का संदेश स्पष्ट है— 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था 20वीं सदी की शक्ति-संरचना के आधार पर नहीं चल सकती । विश्व अर्थव्यवस्था में उपरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए वैश्विक संस्थाओं में भी उनकी आवाज और भागीदारी बढ़नी चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक सहयोग भी होगा। भारत ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश, वित्तीय सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।

भारत की अध्यक्षता में व्यापार मंत्रियों की बैठकों में भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विविध बनाने तथा छोटे एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया है। भारत का अनुभव बताता है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना, विशेषकर डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और तकनीक आधारित सेवाएं विकासशील देशों के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती हैं। इसलिए ब्रिक्स के मंच से भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि तकनीक केवल विकसित देशों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। भारत आज दुनिया के सामने अपनी डिजिटल क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। डिजिटल भुगतान को आम नागरिक तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि ब्रिक्स देश डिजिटल भुगतान, फिनटेक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हैं, तो इससे विकासशील देशों के करोड़ों लोगों को लाभ मिल सकता है। यह भारत की उस सोच से मेल खाता है जिसमें तकनीक का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि आम आदमी का सशक्तीकरण भी है। नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष भारत-चीन संबंध भी है। चीन की भागीदारी इस सम्मेलन को रणनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक अविश्वास के बावजूद हाल के वर्षों में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह चीन के साथ संवाद बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं से समझौता न करे। यही भारतीय कुटनीति की परीक्षा है— प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग और मतभेदों के बीच संवाद भारत यह संदेश देना चाहता है कि किसी देश के साथ आर्थिक या राजनीतिक मतभेद होने का अर्थ यह नहीं कि संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। ब्रिक्स में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका है।

{ विचार पीठ }

दुबई में बजा मोहन का डंका, एमपी में संभावनाएं हैं अपार

नजरिया

प्रदेश में 18 नई उद्योग अनुकूल नीतियां, विस्तृत लैंड बैंक, भरपूर जल उपलब्धता, स्किल्ड मानव संसाधन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों को बेहतर वातावरण प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेश नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग अनुकूल बनाया है। एक दौर था जब एमपी की गिनती बीमारु राज्य के रूप में होती थी, अब उद्योगों के अनुकूल नीति और निवेश

हर्षवर्धन पांडे

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दुबई यात्रा ने राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में एक नए युग का आगाज किया है। वार्षिक निवेश बैठक एआईएम कॉग्रेस 2026 में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य को वैश्विक मंच पर एक सशक्त, भरोसेमंद और संभावनाओं से भरे औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया दुबई दौरा राज्य के आर्थिक विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्र दुबई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की निवेश क्षमताओं को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करते हुए निवेशकों को आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया। यह दौरा न केवल एमपी की छवि को नया रूप देने वाला रहा, बल्कि भविष्य में निवेश के लिहाज से और युवाओं को रोजगार के लिहाज से मध्यप्रदेश के लिए कई संभावनाओं के नए द्वार भी खोलेंगे। मध्यप्रदेश अपनी कई विशिष्ट पहचानों के कारण पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। प्रदेश में 18 नई उद्योग अनुकूल नीतियां, विस्तृत लैंड बैंक, भरपूर जल उपलब्धता, स्किल्ड मानव संसाधन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और पारदर्शी प्रशासन निवेशकों को बेहतर वातावरण प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेश नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग अनुकूल बनाया है। एक दौर था जब एमपी की गिनती बीमारु राज्य के रूप में होती थी, अब उद्योगों के अनुकूल नीति और निवेश की भरपूर क्षमताओं से एमपी देश के साथ ही दुनिया के निवेशकों के दिल जीत रहा है। औद्योगिक इकाईं स्थापित करने के लिए राज्य में अब केवल 29 दिन में जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। मोहन सरकार में लगभग 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। प्रदेश में ऑन द स्पॉट लैंड अलॉटमेंट हो रहा है। मध्यप्रदेश में 1 लाख से अधिक इंस्ट्रियल लैंड बैंक और 5 लाख किलोमीटर से अधिक रोड नेटवर्क है। राज्य सरकार की निवेशकों के अनुकूल नीतियां और अनेक प्रोत्साहन राज्य में व्यापार और उद्योग की नई



संभावनाएं के द्वार खोल रही हैं जिससे निवेशक मध्यप्रदेश की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में कई प्रमुख कंपनियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। दुबई के व्यापारिक समुदाय के साथ हुई बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है, जहां टैक्स ह्यूट, तेज़ मंजूरी प्रक्रिया और कुशल कार्यबल उपलब्ध है।

दुबई प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैश्विक निवेशकों और प्रमुख उद्योग समूहों के साथ वन टू वन बैठकों में लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 53,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगी। शराफ ग्रुप द्वारा रेल-साइडिंग लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए 450 करोड़ रूऔर रिन्यूएबल एनर्जी व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई। वैश्विक लॉजिस्टिक्स दिग्गज डीपी वर्ड नेतृत्व के साथ उच्चस्तरीय चर्चा में पोवारखेड़ा लॉजिस्टिक्स कंपोजिट हब को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन और वेयरहाउसिंग सुविधाओं के साथ एक प्रमुख इनलैंड

खेतों में फसल, आसमान में उतरेगी ऊर्जा

विनोद सिंह

भारत के खेत अब केवल अन्न पैदा करने तक सीमित नहीं रहेंगे। आने वाले समय में यही खेत देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खेत की मिट्टी में फसल लहलहाए और उसी खेत के ऊपर लगे सौर पैनल स्वच्छ बिजली पैदा करें कृषि और ऊर्जा के इस नए संगम को एग्रीवोल्टिक्स कहा जा रहा है। यह अधारणा भारत जैसे देश के लिए विशेष महत्व रखती है, जहाँ एक ओर बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉ. प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में 7वें एग्रीवोल्टिक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026 के कर्टेन रेजक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस दिशा में भारत की भावी नीति का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि जिस किसान ने हल्हसा देश का पेट भर है, वहीं अब देश को रोशन भी कर रहा है। अन्नदाता अब ऊर्जादाता बन रहा है। यह कथन केवल एक भावनात्मक संदेश नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र को ऊर्जा उत्पादन से जोड़कर किसानों की आय में स्थिरता लाने की संभावनाओं की ओर संकेत करता है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम- कुसुम के अगले चरण में एग्रीवोल्टिक्स के लिए एक समर्पित घटक लाया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को खेती जारी रखते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन से आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करना है। इसमें विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सरकारी समितियों और पंचायतों को केंद्र में रखा जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का स्वािमित्व किसान के पास ही बना रहे। भारत की कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी वास्तविकता यह है कि देश के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। ऐसे किसान सीमित भूमि पर खेती करते हैं और उनकी आय काफी हद तक मानसून बाजार भाव तथा कृषि लागत पर निर्भर रहती है। ऐसे में यदि उसी भूमि से निर्भर सौर ऊर्जा आय का एक नया स्रोत जुड़ जाए तो किसान की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। एग्रीवोल्टिक्स का मूल विचार भी यही है कि किसान को फसल और सौर ऊर्जा में से किसी एक का चुनाव न करना पड़े। सौर पैनलों को इस तरह स्थापित किया जाए कि उनके नीचे या आसपास खेती जारी रह सके। यानी जमीन पर फसल और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी से बिजली एक ही छत से दोहरा ली जाए। यही मॉडल सीमित कृषि भूमि के अधिकतम उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। डॉ. जोशी ने एक एकड़ जमीन से



किसान की संभावित तीन आय धाराओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। पहली आय खेत में पैदा होने वाली फसल से होगी। दूसरी आय सौर ऊर्जा को डिस्कॉम को बेचने से प्राप्त हो सकती है। तीसरा लाभ डीजल आधारित सिंचाई की जगह सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से होने वाली बचत के रूप में सामने आएगा। इस प्रकार सौर ऊर्जा किसान के लिए केवल अतिरिक्त कमाई नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का साधन बन सकती है। भारत की जनसंख्या और भूमि का अनुपात भी एग्रीवोल्टिक्स की उपयोगिता को स्पष्ट करता है। भारत में विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी रहती है, जबकि विश्व की कुल भूमि में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2.4 प्रतिशत है। देश के 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं और दो हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कृषि भूमि का ऐसा उपयोग, जिसमें खाद्य उत्पादन प्रभावित किए बिना ऊर्जा उत्पादन भी किया जा सके, आने वाले समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरी ओर भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। देश ने पिछले वर्ष 55.29 गीगा वाटौर गीगावश्र ऊर्जा क्षमता जोड़ी। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि भारत की ऊर्जा व्यवस्था तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। सौर ऊर्जा इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरी है। कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा का प्रसार दिखाई दे रहा है। पीएम- कुसुम के तहत लगभग 29 लाख कृषि पंपों का सोलरीकरण किया जा चुका है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। पिछले वर्ष विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा ने कुल 16.3 गीगावाट का योगदान दिया, जिसमें पीएम- कुसुम से 7.6 गीगावाट और रूफटॉप सोलर से 8.7 गीगावाट शामिल हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को संख्या भी करीब 56 लाख तक पहुंच रही है। हालाँकि एग्रीवोल्टिक्स को केवल सौर पैनल लगाने

की सामान्य तकनीक मानना उचित नहीं होगा। कृषि और सौर ऊर्जा दोनों की जरूरतों को साथ लेकर चलने के लिए क्षेत्रवार और फसलवार वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक होंगे। हर फसल को समान मात्रा में धूप की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह देश के अलग- अलग क्षेत्रों में जलवायु, मिट्टी, वर्षा और तापमान की परिस्थितियाँ भी अलग हैं। इसलिए पैनल की ऊँचाई, उनके बीच की दूरी, दिशा, ट्रैकिंग सिस्टम और संरचना का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप करना होगा। इस दिशा में पुणे स्थित बाएफ के रूरल इनेवेशन सेंटर में 30 फसलों के साथ 17 अलग-अलग सौर बिन्यासों का परीक्षण किया जा रहा है। यह प्रयोग इस बात का उदाहरण है कि एग्रीवोल्टिक्स की सफलता के लिए अनुसंधान और प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। भविष्य में यह तय करना होगा कि किस क्षेत्र में किस फसल के साथ किस प्रकार की सौर संरचना सबसे प्रभावी होगी। कृषि मशीनरी की आवाजों भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।यदि खेत में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या अन्य कृषि उपकरण आसानी से नहीं चल पाएंगे तो किसानों के लिए एग्रीवोल्टिक्स आकर्षक मॉडल नहीं बन सकेगा। इसलिए ऐसी संरचनाओं की आवश्यकता होगी जिनके नीचे कृषि कार्य सामान्य रूप से किया जा सके और जो स्थानीय मौसम की परिस्थितियों का भी सामना कर सके। इसके साथ लागत कम करना भी जरूरी होगा। सौर संरचनाओं, मॉर्डीटॉप सिस्टम और अन्य उपकरणों की लागत यदि अधिक रही तो छोटे किसान के लिए इस मॉडल को अपनाना कठिन हो सकता है। इसलिए उद्योग, स्टार्टअप और शोध संस्थानों को कम लागत वाली, मजबूत और किसान केंद्रित तकनीक विकसित करनी होगी। एग्रीवोल्टिक्स की सफलता के लिए कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऊर्जा क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा फसलवार तथा क्षेत्रवार आंकड़े तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इससे किसानों को यह जानकारी मिल सकेगी कि उनके क्षेत्र में कौन-सी फसल और कौन-सा सौर बिन्यास सबसे उपयुक्त रहेगा। इस नई व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन भी जरूरी है। भारत में लगभग 70 हजार सूर्य मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये प्रशिक्षित युवा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, रखरखाव और तकनीकी सहायता में भूमिका निभा सकते हैं। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। एग्रीवोल्टिक्स की संभावनाएँ केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। डॉ. जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का अनुभव ग्लोबल साउथ के उन देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, जहाँ छोटे कृषि जोत, पर्याप्त

38 साल बाद श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे भारतीय रक्षा मंत्री

नीरज कुमार दुबे

श्रीलंका हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच स्थित है। कोलंबो, हंबनटोटा और अन्य बंदरगाहों की भौगोलिक स्थिति इसे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए असाधारण महत्व देती है। पिछले वर्षों में चीन की आर्थिक और बंदरगाह परियोजनाओं ने श्रीलंका को बीजिंग के रणनीतिक प्रभाव के केंद्र में ला दिया था। करीब 38 साल बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री का श्रीलंका पहुंचना हिंद महासागर की बदलती भू-राजनीति में भारत की उस रणनीतिक वापसी का संकेत है, जिसमें सुरक्षा, समुद्री शक्ति, आर्थिक साझेदारी और जनविश्वास, चारों मोर्चों को एक साथ साधा जा रहा है। इससे पहले 1988 में तत्कालीन रक्षा मंत्री के.सी पंत श्रीलंका गए थे और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोलंबो की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह ने कोलंबो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, उसका रणनीतिक संदेश बेहद स्पष्ट था, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका को अपना बेहद करीबी मित्र मानता है और संकट की किसी भी घड़ी में उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह केवल भावनात्मक बयान नहीं, बल्कि 2022 के आर्थिक संकट और 2025 में चक्रवात दिवाह के बाद भारत की त्वरित सहायता से जुड़ी उस विश्वसनीयता का राजनीतिक विस्तार है, जिसे श्रीलंका में चीन के मुकाबले भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जा सकता है।

श्रीलंका हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच स्थित है। कोलंबो, हंबनटोटा और अन्य बंदरगाहों की भौगोलिक स्थिति इसे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए असाधारण महत्व देती है। पिछले वर्षों में चीन की आर्थिक और बंदरगाह परियोजनाओं ने श्रीलंका को बीजिंग के रणनीतिक प्रभाव के केंद्र में ला दिया था। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम संकेत देता है कि कोलंबो अब एकतरफा चीनी निर्भरता की बजाय प्रतिस्पर्धित साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है। खुद श्रीलंका के संडे टाइम्स ने राजनाथ सिंह के दौर से पहले लिखा कि भारत चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली यात्रा के दौरान हुए समझौतों को तेजी से लागू किया जाए। अखबार ने यह भी रेखांकित किया कि सिंह की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब श्रीलंका को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अधिक सक्रियता से संचालित करना होगा। इसी अखबार के संपादकीय ने इससे भी बड़ा संकेत दिया। उसने हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों, समुद्री मार्गों और बंदरगाहों की भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच श्रीलंका को फिर से जिओपॉलिटिकल बोटेक्स में बताया और चीन के संदर्भ में पहले सामने आए सटिचंग शोष-पोतों के मुद्दे को याद किया। यानी श्रीलंका की अपनी मीडिया बहस भी यह स्वीकार कर रही है कि द्वीप की सुरक्षा और संप्रभुता अब सीधे हिंद महासागर की महाशक्ति प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है। इस यात्रा का सबसे ठोस परिणाम तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों के रूप में सामने आ रहा है। इनमें दोनों देशों के एनसीसी के बीच सहयोग, भारत और श्रीलंका के नेशनल डिफेंस कालेजेज के बीच साझेदारी तथा श्रीलंकाई वायुसेना के भारतीय मूल के ४0 एंटी-एसफ़ाफ्ट हथियारों के रखरखाव में भारत की सहायता शामिल है। भारत पहले ही 24 ऐसे हथियार श्रीलंका को दे चुका है और अब शेष छह की भी मुफ्त में सैटेनैस सहायता करेगा। यहां असली महत्व हथियारों से ज्यादा दीर्घकालिक मैनेज इंटरऑपरेबिलिटी और संस्थागत संबंधों का है। प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा और उपकरणों का रखरखाव किसी देश को केवल हथियार बेचने से कहीं ज्यादा गहरे सुरक्षा रिस्ते में बांधता है। इसके साथ ही कोलंबो बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के आईएनएस उदैगिरि की मौजूदगी ने यात्रा को स्पष्ट समुद्री आयाम भी दे दिया है। राजनाथ सिंह ने केवल रक्षा की भाषा नहीं बोली। उन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता, तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और वैश्विक भूमिका को भी सामने रखा।

जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड एवं निर्यात प्रोत्साहन समिति की हुई बैठक

उद्योग प्रतिनिधियों से कलेक्टर ने किया संवाद

समय जगत, पन्ना। पन्ना कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में गत बुधवार को सायं कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड एवं निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक हुई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पन्ना के तत्वाधान में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में नव उद्यमियों सहित जिले के उद्योग प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस मौके पर शासन की नवीन उद्योग नीति के मुताबिक पन्ना जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी, नवीन उद्यमों को सहूलियत प्रदान करने और प्रत्येक स्तर पर समस्याओं के त्वरित निराकरण के दृष्टिगत सार्वक संवाद किया गया। कलेक्टर श्रीमती परमार ने कहा कि नवीन उद्यम स्थापना के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशासनिक स्तर पर हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में जिले में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास, उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण सहित स्थानीय



उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा जिले से निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। साथ ही उत्पादों और अपने उद्यमों से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। बैठक में लघु उद्योग भारती, फर्नीचर एसोसिएशन,

कैट, लघु उद्योग संघ, व्यापार मंडल, विभिन्न व्यापार समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्य, जिले के गणमान्य उद्यमी एवं व्यवसायी उपस्थित रहे। संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा उद्योगों के विकास एवं निर्यात संवर्धन के लिए संचालित योजनाओं एवं प्रयासों की जानकारी भी दी गई। इस बैठक में उद्यमियों द्वारा उद्ये

गए विषयों पर आवश्यक कार्यवाही एवं संबंधित विभागों के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कैट जिलाध्यक्ष मनोज केशरवानी द्वारा बड़गांव औद्योगिक क्षेत्र में पन्ना के उद्यमियों को प्रार्थमिकता देने का मुद्दा उठाया जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा पन्ना के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित होने वाले उद्यम संवाद को लेकर भी सार्थक विचार विमर्श हुआ। आगामी जनवरी माह में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इवेस्टर्स समिट की महत्वपूर्ण जानकारी से भी उपस्थितजनों को अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य पर एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के तहत एवं उत्कृष्ट नवाचार व स्टार्टअप पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितलाभ का वितरण भी किया गया।

गर्भवती महिलाओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

दमोह, समय जगत। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश राय ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को समय पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक जांच एवं उचित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले में विशेष स्वास्थ्य जांच क्लिनिक आयोजित किए गए। अभियान के तहत 471 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई तथा आवश्यकतानुसार परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रार्थमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चिकित्सक एवं सीएचओ द्वारा क्षेत्र में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच के



साथ ही सप्ताह के दौरान चिन्हित नई गर्भवती महिलाओं की भी जांच की गई। जांच के दौरान गर्भावस्था में संभावित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार, परामर्श एवं उचित स्वास्थ्य संस्थान पर रेफरल की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

आगामी सप्ताह में संभावित प्रसव तिथि इंडेडी वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच भी की गई जिससे प्रसव के पूर्व आवश्यक तैयारियां एवं समय पर चिकित्सकीय सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। गर्भवती महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर

पौष्टिक स्वल्पाहार, पृथक पंजीयन काउंटर, पर्याप्त बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीएमएसएमए के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर गर्भवती महिला की समय पर जांच हो जोखिम की समय रहते पहचान हो और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपचार एवं विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हों। सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ मां-बच्चे के लिए नियमित प्रसवपूर्व जांच को अभियान का प्रमुख आधार बनाया गया है। अभियान के अंतर्गत सिविल अस्पताल हटा में डॉ. भूमिजा राजपूत, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पथरिया में डॉ. प्रियंका छबड़ा, पंथरा में डॉ. गीताजोति सिद्धम, तेनुखेड़ा में डॉ. कुलदीप अजमानी तथा हिण्डौरिया में डॉ. ज्योति दुबे ने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए गर्भवती महिलाओं की जांचएं उपचार एवं आवश्यक परामर्श दिया।

संक्षिप्त समाचार

दस्तक अभियान के तहत विद्यार्थियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण का संदेश

दमोह, समय जगत। दस्तक अभियान के अंतर्गत हाथ धोने के महत्वपर स्वच्छता एवं पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से टीम द्वारा स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से दमोह जिले के विभिन्न ब्लॉकों के माध्यमिक विद्यालयों में जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। गतिविधि के दौरान चित्र काई के माध्यम से कहानी एवं संवादात्मक प्रस्तुतीकरण के द्वारा विद्यार्थियों को प्रमुख स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी संदेश प्रभावी रूप से प्रदान किए गए। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता द्वारा होल तैयार करने की विधि तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हाथ धोने की सही एवं निर्धारित प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।

चंबल के बीहड़ों में 14 को लगेगा माता पार्वती का एक दिवसीय मेला

समय जगत, श्यापुर। चंबल के बीहड़ों में विराजमान मां पार्वती के मंदिर पर 14 सितंबर, सोमवार को एक दिवसीय धार्मिक मेला लगेगा। भादौ अमावस्या के बाद पहले सोमवार को होने वाले इस मेले में रघुनाथपुर सहित श्यामपुर, नदीगांव, घूमस, ओछापुरा, हीरापुरा और ढोढर क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे। ग्राम पंचायत जमूदी ने मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगेगी। लोग मां पार्वती के दर्शन कर पूजा-अर्चना और मंत्रों मांगेंगे। मेले की सबसे खास परंपरा सूर्यास्त से जुड़ी है। शाम ढलने से पहले श्रद्धालु और दुकानदार मंदिर परिसर छोड़कर लौट जाते हैं। सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर पूरी तरह खाली हो जाता है और रात में किसी व्यक्ति के रुकने की अनुमति नहीं रहती। ग्रामीणों के अनुसार मेले में कुंवारी कन्याओं द्वारा मां पार्वती का श्रृंगार करने की भी पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि माता का श्रृंगार कर पूजा करने से विवाह की मनोकामना पूरी होती है।

अवैध रेत खनन एवं परिवहन की शिकायत के लिए अब क्यूआर कोड हुआ जारी

समय जगत, श्यापुर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभ्यारण क्षेत्र में अवैध रेत खनन, परिवहन, शिकार, अतिक्रमण तथा अन्य पर्यावरणीय अपराधों और गतिविधियों की सूचना क्यूआर कोड के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा राजेश कुमार गंगोले ने बताया कि वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभ्यारण क्षेत्र में अवैध रेत खनन से संबंधित गतिविधियों तथा अवैध रेत परिवहन, शिकार, अतिक्रमण आदि की सूचना के लिए क्यूआर कोड जारी किया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कोई भी नागरिक उक्त संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं। इसके माध्यम से अवैध रेत खनन, अवैध रेत परिवहन, वन्य जीव शिकार, अतिक्रमण एवं अन्य पर्यावरणीय अपराधों की सूचना आवश्यकतानुसार फोटो, वीडियो एवं जीयो टैग इफॉर्मेशन सहित उपलब्ध कराई जा सकती है।

छिमछिमा हनुमान मंदिर पर आज लगेगा मेला, दर्शन करने पहुंचेंगे लाखों लोग भजन, गीत-संगीत व विशाल भंडारे का होगा आयोजन

समय जगत, श्यापुर। विजयपुर तहसील क्षेत्र के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र छिमछिमा हनुमान मंदिर पर प्रति वर्ष लगने वाला छिमछिमा हनुमान मेला इस बार 12 सितंबर को लगेगा। इस मेले में भजन, संगीत, कीर्तन आदि प्रतियोगिताएं भी होगी, जिन्हें बड़ी संख्या में संगीतप्रेमी भाग लेंगे। मंदिर पर बैराड़ सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारा किया जाएगा। विजयपुर की सीमा पर स्थित छिमछिमा हनुमान मंदिर मेले में भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसकी तैयारियां पूरी ली गई है। दिन भर चलने वाले भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने हजारों भक्तों का आना होता है, जिसे लेकर



संबंधितों को दायित्व सौंप गए हैं। मेले में छिमछिमा हनुमान के दर्शन करने दूर-दराज के भक्तों का भी आना होता है, जिसके इंतजामात किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के

मुताबिक भारत में जब मुगल साम्राज्य था, उस समय संत समर्थ गुरु ने जगह-जगह हनुमान प्रतिमाओं की स्थापना की। इसी के तहत विजयपुर से 9 किलो दूर घने जंगल में छिमछिमा हनुमान की स्थापना हुई। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब ने पूरे भारतवर्ष में मूर्त और मंदिर तोड़ने का अभियान चलाया था, उस समय मुगल सेना यहां भी आई। हनुमान जी की कृपा से मंदिर के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में चारों ओर की जमीन मोम की हो गई, जिससे औरंगजेब की सेना आगे नहीं बढ़ सकी। मान्यता है कि हनुमान जी ने प्रकट होकर सेना को अधा कर दिया।

संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने रखे श्यापुर के विकास पर विचार

समय जगत, श्यापुर। जेसीआई श्यापुर द्वारा जेसीआई वीक के अंतर्गत गुरुवार को 'युवा संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को श्यापुर शहर की वर्तमान समस्याओं, राजनीति और भविष्य के श्यापुर को लेकर अपने विचार एवं समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा नेता एवं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संजय मंगल तथा विशिष्ट अतिथि वैभव राठौर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी युवाओं ने विभिन्न चरणों में श्यापुर की वर्तमान समस्याएं एवं उनके समाधान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्यापुर की राजनीति तथा भविष्य का श्यापुर जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका संजय महाना एम माया राजकुमार शर्मा ने निभाई।

महिला ने लगाया धमकी देने का आरोप आरोपी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर दिया आवेदन

विदिशा, समय जगत। गुरुवार को आनंदपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कांछीखेड़ा निवासी एक परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को दोपहर करीब 11.30 बजे उनकी पति घर पर अकेली थी और बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर कोशल पाटीदार उनके घर आए और दरवाजा लगाकर महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती करने लगे। इसी दौरान महिला द्वारा चिल्ला चोट की गई तो वह घर से भाग गए। महिला ने बताया कि उनके पति मजदूरी करने के लिए राजस्थान गए हुए थे और उनके बच्चे भी घर पर नहीं थे, इसी का फायदा उठाकर वह घर में घुस गए और उनके



साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत करने के लिए वह आनंदपुर थाने में गए थे, लेकिन वहां से उन्हें शमशाबाद थाना भेज दिया गया। जहां विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया

गया है। महिला ने बताया कि आरोपी द्वारा उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई लेकिन निष्पन्न चोट होने के कारण वह भाग गया। पुलिस द्वारा छोटी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आवेदन देकर पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस मामले की जांच कराई जाए और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान आरोपी द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष उनके साथ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और मामले को गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

रेत के स्टॉक में भारी गड़बड़ी पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

विस्टा सेल्स पर 21.79 करोड़ की शास्ति अधिरोपित

सैंड पोर्टल और मौके के स्टॉक में 1.16 लाख घनमीटर से अधिक का अंतर वैध परिवहन के दस्तावेज नहीं दे सका फर्म संचालक

समय जगत, कटनी। खनिज रेत के भंडारण और परिवहन में अनियमितता के मामले में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 21 करोड़ 79 लाख 77 हजार 525 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई सैंड पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और मौके पर भौतिक सत्यापन में मिले रेत स्टॉक के बीच 1 लाख 16



हजार 254.68 घनमीटर के अंतर के आधार पर की गई। प्रकरण के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 तहसील बड़वारा के ग्राम गुड़ुआला के खसरा क्रमांक 137, 200 रकबा 1.65 हेक्टेयर स्थित मेसर्स विस्टा सेल्स के खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति स्थल का खनिज निरीक्षक

द्वारा निरीक्षण किया गया। भौतिक सत्यापन में मौके पर करीब 1,990 घनमीटर रेत मिली, जबकि 30 सितंबर 2023 की रात तक सैंड पोर्टल पर 1 लाख 18 हजार 244.68 घनमीटर स्टॉक दर्ज था। इस तरह 1 लाख 16 हजार 254.68 घनमीटर रेत स्टॉक का अंतर पाया गया। कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई करते हुये कलेक्टर श्री तिवारी के समक्ष विस्टा सेल्स की ओर से मापन प्रक्रिया और अवैध परिवहन के प्रत्यक्ष प्रमाण पर सवाल प्रत्यक्ष प्रमाण पर बचाव पक्ष ने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी वाहन की जल्ती या विशिष्ट अवैध परिवहन का साक्ष्य नहीं पाया गया है। इस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान कलेक्टर न्यायालय ने कहा कि निरीक्षण से पहले परिवहन होने की स्थिति में मौके पर वाहन की जल्ती आवश्यक नहीं है। पोर्टल और भौतिक सत्यापन के बीच पाया

गया। न्यायालय के समक्ष विस्टा प्रा. लिम. फर्म द्वारा इतनी बड़ी मात्रा के रेत स्टॉक अंतर का कोई विश्वसनीय एवं विधिसम्मत दस्तावेजी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी आधार पर उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर कलेक्टर श्री तिवारी ने 1 लाख 16 हजार 254.68 घनमीटर रेत पर 125 रुपये प्रति घनमीटर की रॉयल्टी के अनुसार 1 करोड़ 45 लाख 31 हजार 835 रुपये की रायल्टी का 15 गुना 21 करोड़ 79 लाख 77 हजार 525 रुपये की अर्थशास्ति अधिरोपित किया है। साथ ही अधिरोपित शास्ति जमा करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 19 के तहत बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन पर रॉयल्टी की 15 गुना अर्थशास्ति का प्रावधान है।

मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान कई वाहनों के बने चालान

विदिशा, समय जगत। गुरुवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में न्यायालय के पास मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा वाहनों को रोककर न्यायालय परिसर में भेजा गया, जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वाहनों के दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की गई। मजिस्ट्रेट चेकिंग में सीजेएम रमाकांत भारक, जेएमएफसी शिवांगी सिंह और जेएमएफसी दीक्षा रावैर मौजूद रहें। चेकिंग की कार्रवाई शाम 4.30 बजे से 6 बजे तक चली। इस दौरान यातायात पुलिस और सिविल लाइन पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। चेकिंग के दौरान कुल 120 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 15 वाहन चालकों के विरुद्ध मौके पर कार्रवाई करते हुए कुल 4500 रुपए का शमन शुल्क वसूला गया, जबकि 105 वाहन चालकों को आगामी लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। वाहन चालकों के



दस्तावेजों में कमी, यातायात नियमों का उल्लंघन सहित अन्य मामलों की जांच की गई। जांच के दौरान मोटर साइकिल पर तीन सवारी बैकवर वाहन चलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को रोककर उनके खिलाफ नियमानुसार चालान बनाए। वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, निर्धारित क्षमता के अनुसार सवारी बैठाने और यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान स्कूल और कॉलेज की बसों को भी जांच के दायरे में लिया गया। बसों के आवश्यक दस्तावेजों सहित अन्य

निर्धारित मापदंडों की जांच की गई। संबंधित बस चालकों और संचालकों को विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। मजिस्ट्रेट चेकिंग की जानकारी लगने के बाद कुछ वाहन चालक कार्रवाई से बचने के लिए मुख्य मार्ग से न जाकर आसपास की गलियों से अपने वाहन निकालते हुए नजर आए। वहीं न्यायालय परिसर में जांच के लिए बड़ी संख्या में वाहन पहुंचने के कारण कुछ समय तक वाहनों की कतार लगी रही। न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस तरह की मजिस्ट्रेट चेकिंग की जाती है।

इटारसी में फरारी काट रहा था हत्या का आरोपी, पांच साल बाद रीठी पुलिस ने किया गिरफ्तार

समय जगत, कटनी। पिछले पांच साल से हत्या के मामले में फरार आरोपी को रीठी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रीठे थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद ने बताया कि 2 फरवरी 2022 को चरसलाल पारधी पिता रामरस पारधी निवासी ललितपुर बूढ़ा की मौत हो गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी जोनस लाल पारधी, रूलबाबू पारधी एवं चंस्पर उर्फ बिस्किटलाल पारधी द्वारा लोहे की रॉड एवं बरछी से मारपीट कर चरसलाल पारधी की हत्या कर दी गई थी। घटना के दौरान बीच बचाव करने आए अजूबा पारधी एवं टट्टी पारधी के साथ भी मारपीट की गई। घटना के संधर्भ में रीठी थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा लगातार उनकी तलाश एवं संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। आरोपी पारधी समुदाय से होने के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे,



जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी में कठिनाई आ रही थी। काफी प्रयासों के बावजूद आरोपियों के नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में फरारी चालान प्रस्तुत किया गया। रीठी पुलिस द्वारा लगातार फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि हत्या के प्रकरण में फरार आरोपी रूलबाबू पारधी वर्तमान में

इटारसी जिला नर्मदापुरम में मौजूद है। सूचना की तत्परीक कर पुलिस टीम को तत्काल इटारसी रवाना किया गया। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी रूलबाबू पारधी को इटारसी रेलवे स्टेशन के पास से 5 वर्ष बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

